कम्प्यूटर क्रांति की गति

*148. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में पिछले दिनों जो कम्प्यूटर क्रांति की गति थी वह गति अब थम गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इंटरनेट पर भीड़भाड़ के कारण इस पर काम करना दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ग्राहकों से मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु॰ तिरुनावुक्करसर): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्तमान कम्प्यूटर क्रांति थम जाने की बजाए इससे देश में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार हुआ है, जैसाकि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है:—

* कम्प्यूटरों का प्रयोग उपक्रम सेवाओं, विनिर्माण, सरकार, मनोरंजन एवं शिक्षा के नए क्षेत्रों में होना आरम्भ हो गया है।
* सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख नागरिक केन्द्रित अनुप्रयोगों का कार्यान्वयन भू-अभिलेख, पंजीकरण, पासपोर्ट, रेलवे आरक्षण, सड़क कर एवं ड्राइविंग लाइसेंस, उपयोगिता बिल निर्माण, बैंकिंग तथा बीमा में किया गया है।
* विभिन्न क्षेत्रों के प्रयोगकर्ताओं को उच्चतर अभिकलन शक्ति और भी कम खर्च पर उपलब्ध है।
* प्रयोक्ता उपयोगी सॉफ्टवेयरों से सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार में सहायता मिली है।
* भारतीय भाषा सॉफ्टवेयर साधनों ने कम्प्यूटरों पर प्रभावी रूप से कार्य करने की क्षमता उपलब्ध कराई है जिससे भारत की गैर-अंग्रेजी भाषी जनता सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ उठा सकें।

* वैयक्तिक कम्प्यूटरों की बिक्री, जो सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार का एक पैमाना है, में वर्ष 1997 से 2003 तक की अवधि के दौरान 23 प्रतिशत की दर से वार्षिक संचयी वृद्धि हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार बढ़ने के कारण एक उद्योग का निर्माण हुआ है, जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 6,50,000 कार्मिक तथा विशेषज्ञ नियोजित हैं और जो भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 2.4 प्रतिशत तथा इसके निर्यात में 20.4 प्रतिशत का योगदान करता है।

(ख) इन्टरनेट एक सर्वोत्तम प्रयास सेवा है जिसमें कुछ परिस्थितियों में भीड़-भाड़ की संभावना रहती है। इन्टरनेट के प्रयोग तथा प्रसार में वृद्धि से उच्चतर बैण्डविड्थ की उपलब्धता आवश्यक हो जाती है। इसको पूरा करने के लिए कई सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की दूरसंचार कम्पनियों द्वारा देश में लगभग 5,00,000 रूट किलोमीटर के प्रकाशिक तंतु बिछाए गए हैं। सामान्य तथा मोबाइल दूरसंचार सेवाओं में पिछले 3 वर्षों के दौरान 24प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई है जिससे कुल 66 मिलियन लाइन टेलीफोन नेटवर्क का निर्माण हुआ है। प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में समुद्रतलीय केबल लैण्डिंग का प्रयोग करके अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे की स्थापना की गई है और प्रणाली के प्रयोग की क्षमता बढ़कर 9.92 गीगाबिट् प्रति सेकेण्ड हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, इन्टरनेट सेवा प्रदातागण बैण्डविड्थ की उपलब्धता तथा सर्वरों और नेटवर्कों की क्षमता में भी वृद्धि करके प्रयोक्ताओं को इन्टरनेट की अधिगम्यता उपलब्ध कराने में समर्थ हुए हैं। इसके अलावा, प्रयोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं को सेवा की क्वालिटी के संबंध में संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने इन्टरनेट सेवाओं के लिए सेवाओं की गुणवत्ता के मानदण्ड निर्धारित किए हैं।

(ग) और (घ) दूरसंचार का प्रशुल्क आदेश (टीटीओ), 1999 में इस समय इन्टरनेट सेवाओं के लिए कोई प्रशुल्क अधिसूचित नहीं किया गया है। इससे इन्टरनेट सेवा क्षेत्र में मुक्त प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है, जिसमें लगभग 200 इन्टरनेट सेवा प्रदाता हैं। प्रत्येक इन्टरनेट प्रदाता अपने प्रयोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें बाजार की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित प्रशुल्क के चयन का विकल्प दिया जाता है जिसे टीआरएआई के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

Pace of computer revolution

†*148. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

†Original notice of the question was received in Hindi.

(a) whether it is a fact that the pace of computer revolution that was there in the country sometime back has come to a halt now;

(b) if so, whether it is also a fact that due to the crowd on the net, the working on internet is becoming difficult day-by-day;

(c) whether it is also a fact that all the internet service providers are charging arbitrarily; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Far from coming to a stop, the ongoing computer revolution has led to the proliferation of information technology (IT) in the country, as evidenced by the following facts:—

* The usage of computers has extended to new domains in Enterprise Services, Manufacturing, Government, Entertainment and Education.
* Major citizen centric applications of IT have been implemented in land records, registration, passport, railway reservation, road tax and driving licence, utility billing, banking and insurance.
* Higher computing power is available at a more affordable cost to diverse user sectors.
* User friendly softwares have facilitated the dissemination of IT.
* Indian language software tools have provided effective interface on computers to enable the non-English speaking population of India to benefit from IT.
* The off-take of personal computers, which is a measure of IT penetration, has registered a compound annual growth rate of 23% during the period 1997—2003.

The increased IT penetration has helped create an industry, which

employs 6,50,000 workers and professionals directly or indirectly and makes a contribution of 2.4% to India's GDP and of 20.4% to its exports.

(b) Internet is a best effort service with a probability of congestion in certain situations. The increase in the penetration and usage of the Internet necessitates higher bandwidth availability. To address this, nearly 5,00,000 route kilometres of optical fibre have been laid in the country by a number of public and private Telecommunications companies. Basic and mobile telecommunication services have grown at an average rate of 24% in the last 3 years, aggregating to a 66 million line telephone network. International gateways have been set up, using sub-marine cables landing at major Indian ports, and the system capacity used has gone upto 9.92 gigabits per second. As a result, the Internet Service Providers have been able to offer internet accessibility to the users by enhancing bandwidth availability and the capacity of the servers and the networks. Further, with a view to sensitizing the users as well as the service providers to the imperatives of the service quality, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has prescribed Quality of Service norms for Internet Services.

(c) and (d) The Telecom Tariff Order (TTO), 1999 for the time being, has not notified any tariff for Internet Services. This has encouraged an open competition in the Internet Services sector, which comprises nearly 200 Internet Service Providers. Every Internet Service Provider offers a variety of services to its users with a choice of market determined tariffs which have to be filed with the TRAI.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, यह कंप्यूटर क्रांति का जमाना है। शुरू के दिनों में जब कंप्यूटर आया तो सारी दुनिया में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल इंटरनेट पर होता था। बाद में जर्मनी, फ्रांस और चीन ने अपनी भाषा का सॉफ्टवेयर बनाया। लेकिन आज भी हिन्दुस्तान की कोई भी भाषा, संविधान के हिसाब से चाहे राष्ट्रभाषा हिन्दी कही जाती हो या कोई भी मातृभाषा कही जाती हो, वह कंप्यूटर में नहीं आ पाई है। इस जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि भारतीय भाषा सॉफ्टवेयर साधनों ने कंप्यूटरों पर प्रभावी रूप से कार्य करने की क्षमता उपलब्ध कराई है जिससे कि भारत की गैर-अंग्रेजी भाषी जनता सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ उठा सकें। एक ओर हम भारतीयों को गैर अंग्रेजी भाषी जनता कहा जा रहा है। दूसरी ओर किसी भी भाषा में – मायने हजार साइट निकल जाएं तो मुश्किल से कोई एक हिन्दी की साइट मिलती है। क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि दूसरे देश इस कंप्यूटर क्रांति के जमाने में जब अपने देश की भाषा को पैठ दिला रहे हैं, तब क्या हम भी उस दिशा में प्रयास करेंगे और कर रहे हैं?

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Sir, it is true that in earlier days, the computer users have to operate computers through English softwares only. Now, not only in the national language, Hindi, but also in the regional languages like Tamil, Telugu, etc., computer softwares are being develped. The Central Government is encouraging this. Most of the State Governments are involved in developing softwares in regional languages. The IT Department is assisting the State Governments in all the ways to develop regional language softwares. Slowly, one by one, it is coming in all the regional languages. It is not a situation that only English-knowing people can operate the computers now. There is a change. Now, in majority of the States softwares are being developed in regional languages.

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए बता दूं कि एक "C-DAC" का सॉफ्टवेयर होता है, पता नहीं वे जानते हैं या नहीं, अगर उस में अंग्रेजी में टाइप किया जाए और हिंदी का बटन दबा दिया जाए तो मैटर हिंदी में आ सकता है, अगर तमिल का बटन दबाया जाए तो हिंदी में आ सकता है। महोदय, वह सॉफ्टवेयर महंगा होता है, इसलिए हिंदुस्तान में उस का इस्तेमाल मामूली तौर पर नहीं हो पा रहा है। तो क्या सरकार कम्प्यूटर क्रांति को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए "C-DAC" सॉफ्टवेयर को खास तौर से बड़ी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं में चालू करवाएगी?

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Sir, as I told earlier, not only in C-DAC but also in other places IT computers in Hindi and other languages are being developed. The cost is more and it is not utilised to the maximum. It is true. We are giving due attention to it, trying to reduce the cost and increasing the softwares, as far as regional languages are concerned.

SHRI ROBERT KHARSHIING: Sir, in connection with Question No. 148(a) can the Hon. Minister assure this House that since after radio technology came the telephone technology followed by the tape-recorder technology, then the television technology and now the information technology and after information technology, there will definitely come another new technology, may we know from the hon. Minister whether the Government has any far-sighted approach through planning, research and development and whether it would be willing to consider renaming the IT Ministry as ET (Emerging Technology) Ministry so as to position itself at the cutting edge of technological developments so that India can be at the forefront of any new emerging technological inventions?

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Hon. Chairman, Sir, India is already in the forefront of information technology, all inventions and new developing technologies. I substantiate this with the following facts. In the case of computers, in 1998, the consumption was only 10 lakhs. Now, in 2003, it is 23 lakhs. The contribution of IT to the Gross Domestic Production (GDP) was Rs. 17,58,207... (*Interruptions*)... I am telling you about the advancement that is taking place in India in all the fields, in IT, in computer, in software exports. The export of softwares, which was only Rs. 10,000 crores in 1996-97, is now Rs. 47,000 crores. (*Interruptions*)...

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: What is the main question?

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: I am coming to that.

SHRI ROBERT KHARSHIING: My question is whether the IT Ministry will be renamed as the ET Ministry.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: What is there in the name? Sir, there is no proposal to change the name. The hon. Member wanted to know whether its name could be changed. The Research and Development of the IT Department is concentrating on new technologies. We are not lagging behind. Whatever advancement in technology is being made in developed countries, we are updating our technology accordingly. As on date, we are the frontrunners in technological development.

SHRI B.J. PANDA: Sir, in regard to Internet congestion, the hon. Minister in his answer has said that international gateways have been set up using the submarine cables at major ports. Unfortunately, the bandwidth obtained from these connections are not made available to most of the places in the country. Places like Orissa, Bihar and Jharkhand depend on satellite earth stations. The Internet Service Providers take many months to get permission to set up satellite earth stations. What is the average time taken to give permission to set up a satellite earth station? Will you take some measures to ensure that it comes down to a few weeks, instead of many months?

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Sir, Internet is a best effort service with a probability of congestion in certain situations. To address this problem, nearly five lakh route kilometres of optical fibre has been

laid in the country. So far as the time limit is concerned, I do not have the exact figures with me.

SHRI B.J. PANDA: Please give an undertaking that it will be reduced.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Sir, not only time limit, even rate is also getting reduced. Normally, it takes eight months. We are trying our level best to reduce the time limit and also the rate.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Mr. Chairman, Sir...

श्री सभापति: नेक्स्ट क्वैश्चन। ...(व्यवधान)... अगर आप इस पर जानकारी करना चाहते हैं तो इसी क्वैश्चन पर एक हाफ एन आवर डिसकशन के लिए लिखकर दे दीजिए। माननीय मंत्री जी भी तैयार रहेंगे और मैं एलाऊ कर दूंगा।

New prices of wheat and rice

*149. SHRI EKANATH K. THAKUR: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have announced new prices for wheat and rice at which exporters can lift from the Central Pool; and

(b) if so, the new prices and the stock of wheat and rice with Government?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No, Sir.

In 2000-2001, the export of foodgrains was allowed from the Central Pool in view of the surplus stocks available. In order to promote and facilitate exports, certain post delivery expenses to cover cleaning, upgrading, fumigation, handling, etc., are allowed to the exporters. An Inter-Ministerial High Level Committee of the FCI makes suitable recommendations to the Government in this regard.

The stocks in the Central Pool including with the State Agencies as on 1st November, 2003 were 164 lakh MTs of wheat and 109 lakh MTs of rice.